

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, उमरिया, म0प्र0।

विषय:- उमरिया जिले में करकेली-घुलघुली रहठा-कठौतिया मार्ग उन्नयन/ चौड़ीकरण कार्य कराये जाने हेतु 0.7125 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 0.7875 हेक्टेयर) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स.) संभाग, उमरिया को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/46569/2020)

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, शहडोल का पत्र क्रमांक/मा0चि0/2021/550 दि018.01.2021

-0-

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक, शहडोल एवं आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गाइड लाईन, 2019 अनुसार 01 हेक्टेयर तक वन भूमि में प्रत्यावर्तन के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त है। राज्य शासन की ओर से उपरोक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 2- NPV: Net Present Value(NPV) amount of Rs. 4,46,025/- for the 0.7125 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
- 3- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- 4- प्रकरण में 04 वृक्ष काटे जाना है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों का 10 गुना रोपण 40 वृक्षों का रोपण या न्यूनतम् 100 पौधे लगाने होते हैं। अतः प्रकरण में 100 पौधे की राशि 2,00,000/- कैम्पा मद में जमा कराई जावे।
- 5- User agency shall restrict the 04 no. felling of trees.
- 6- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

-2-

- 7- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. This certificate should be uploaded on portal with compliance report.
- 8- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 9- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 10- No labour camp shall be established on the forest land.
- 11- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 12- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 13- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 14- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 15- The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

उपरोक्तानुसार वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त करें एवं एन.पी.व्ही. की राशि 4,46,025/- तथा 100 वृक्षों की क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि 2,00,000/- आवेदक संस्थान से ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करावें। तत्पश्चात स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन आवेदक संस्थान से कराकर पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड कराने के उपरांत इस कार्यालय को भिजवाये। जब तक इस कार्यालय द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है तब तक आवेदक संस्थान को कार्य करने/क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति जारी न की जावे।



(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11-2-21

पृ. क्रमांक/एफ-5/994/2021/10-11/666
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त, शहडोल, मध्यप्रदेश।
 2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स.) संभाग, उमरिया, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल